an>

Title: Need to ensure appropriate utilization of funds under various schemes for Panchayati Raj Institutions and for rural development in Maharashtra.

श्री राजू शेट्टी (हातकंणंगले) : केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2008 में पूरे देश में ग्राम पंचायतों को कम्पयूटर (संगणक) सेवा से जोड़ने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था । उसके तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को करोड़ों रूपयों कि निधि आवंटित की थी । ग्राम पंचायत का कारोबार पूरे तरीके से ऑन लाईन होना चाहिए, यह उद्देश्य उस योजना के पीछे था । इसके तहत पंचायत की तरफ से दिए जाने वाले दाखिले और दस्तावेज (कागजात) आम जनता को इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध करने का भी उद्देश्य था।

हमारे महाराष्ट्र सरकार और टाटा कन्सलटेंसी इनके ज्वाइंट व्हेंचर से " महाऑन लाईन " नामक कंपनी का निर्माण किया गया । इस कंपनी ने ग्राम विकास मंत्रालय की मदद से महाराष्ट्र राज्य में 32 हजार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की । इन ऑपरेटर्स को हर माह 8,000/- (आठ हजार रूपये) मेहनताना देने का सरकार ने लिखित आदेश में स्पष्ट रूप से जारी किया था । लेकिन उसके बावजूद पहले दिन से ही 8,000/- रूपयों की जगह 4,000/- (चार हजार रूपये) की रकम "महा ऑन लाईन" नामक कंपनी ने अपनी तरफ से डेटा ऑपरेटर्स को बिना बताए डायव्हर्ट कर ली । यह चौंकाने वाली खबर पूरे महाराष्ट्र में फैल गई है और इसी संदर्भ में यह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स लगातार पिछले छह महीनों से आंदोलित है ।

केन्द्र सरकार से ग्राम विकास मंत्रालय की तरफ से चलायी जा रही योजनाओं में ही पैसों का सही विनियोग नहीं हो रहा है । इस तरह की शिकायतें बार-बार आ रही है और वो इस घटना से साबित हो रहा है ।

इसलिए मेरी ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह मांग है कि महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गत 10 वर्षों में जो केन्द्र सरकार की विविध योजनाओं की निधि का सही ढग से उसी नियोजित काम के उपर गाइड लाईन की तहत खर्च हुआ है, इस मामले की जांच कराना नितान्त आवश्यक है ।